के.एस.के.

पूरी बेंच

स्कैमशेर बहादुर, पी. सी. पंडित और पी. डी. शर्मा, जे.जे. के समक्ष

मोती राम और अन्य,-अपीलकर्ता

बनाम

बखवंत सिंह और अन्य,-प्रतिवादी

1964 का पत्र पेटेंट अपील संख्या 340

29 सितम्बर 1967

पंजाब प्री-एम्पशन एक्ट (1913 का 1) - धारा 13 और 15 - भाई - चाहे इसमें सौतेला या सौतेला भाई शामिल हो - बेटा - चाहे इसमें सौतेला बेटा शामिल हो - कुछ विक्रेताओं से संबंधित प्री-एम्प्शन -क्या विक्रेता के शेयर की बिक्री को प्री-एम्प्ट किया जा सकता है, जिससे वह इस प्रकार संबंधित नहीं है कि उसे प्री-एम्प्शन का अधिकार दिया जा सके।

माना गया कि पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट, 1913 की धारा 15 के संदर्भ में "भाई" शब्द में सौतेला या सौतेला भाई शामिल है। भाई ने न्यायशास्त्र की सभी प्रणालियों में 'सौतेले भाई' को शामिल किया है और एक विपरीत इरादे को स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। केवल सौतेले भाई का बहिष्कार किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं होगा

मोद राम और अन्य बनाम बखवंत सिंह और अन्य (शमशेर बहादुर, जे.) ने प्री-एम्प्शन के कानून पर आपत्ति जताई और प्रतिबंध लगाया, जिसे एक समुद्री अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। जहां क़ानून ने एक भाई को और वास्तव में सौतेले भाई से अधिक दूर के रिश्ते को सुरक्षा दी है, सौतेला भाई बहिष्कार का पात्र नहीं हो सकता था। एक श्रेणी के रूप में 'भाई' को छूट का अधिकार दिया गया है जिसमें सौतेला या सौतेला भाई भी शामिल है।

माना गया कि, पंजाब प्री-एम्पशन अधिनियम, 1913 की धारा 15 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के तहत, पंजाब प्री-एम्प्शन (संशोधन) कला, 1964 के 13 द्वारा संशोधित, किसी अन्य पत्नी से महिला विक्रेता के पति के बेटे को ऐसी महिला द्वारा उस भूमि या संपत्ति की बिक्री से पहले छूट देने का अधिकार है जो उसे अपने पति से विरासत में मिली है।

यह माना गया कि सफल होने के लिए, एक प्री-एम्प्टर को विक्रेता के साथ और प्रत्येक विक्रेता के साथ संयुक्त बिक्री के मामले में अपना संबंध स्थापित करना होगा। हालाँकि, प्री-एम्प्शन का अधिकार आम तौर पर प्री-एम्प्शन के अधिकार की सीमा तक ही सीमित होता है और वह पूरे सौदे का दावा

करने का हकदार नहीं होता है जब उसका प्री-एम्प्शन का अधिकार बेची गई संपत्ति के केवल एक हिस्से तक ही सीमित होता है। एक से अधिक विक्रेताओं द्वारा संयुक्त बिक्री के मामले में, एक पूर्व-खालीकर्ता केवल उस विक्रेता या विक्रेताओं के हिस्से को पूर्व-खाली करने का हकदार है जिनसे वह संबंधित है या जिसके माध्यम से वह अपने अधिकार का दावा करता है।

माननीय श्री डी. फाल्शॉ, मुख्य न्यायाधीश और माननीय श्री न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना की खंडपीठ के आदेश दिनांक 14 अप्रैल, 1966 द्वारा मामले को कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए पूर्ण पीठ को भेजा गया। मामले में शामिल.

मामले का निर्णय अंततः 29 सितंबर, 1967 को माननीय श्री न्यायमूर्ति शमशेर बहादुर, माननीय श्री न्यायमूर्ति पी.सी. पंडित और माननीय श्री न्यायमूर्ति पी.डी. शर्मा की पूर्ण पीठ द्वारा किया गया।18 सितंबर, 1964 को 1962 के आरएस.एजे नंबर 1478 में पारित माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.के. महाजन के फैसले और डिक्री के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत लेटर्स पेटेंट अपील।

अपीलकर्ताओं के लिए दलीप चंद गुप्ता, और जतिंदर वीर गुप्ता, वकील।

प्रतिवादियों की ओर से के. एल. सचदेव और बी. आर. कपूर, अधिवक्ता।

पूर्ण पीठ का निर्णय

'शमशेर बहादुर, जे.–

इस विचार के चलते कि महाजन, जे. के निर्णय से इस लेटर्स पेटेंट अपील में निर्णय की मांग करने वाले कुछ प्रश्नों में कठिनाई के बिंदु शामिल हैं, मुख्य न्यायाधीश फाल्शॉ और खन्ना, जे. की खंडपीठ ने इसे निपटान के लिए पूर्ण पीठ को भेज दिया है।

गांव ठुल्लेवाल में खसरा नंबर 871 और 877 में 12 बीघे और 10 बिस्वा जमीन इंद्र कौर और उनके दो बेटों बलकार सिंह और नछत्तर सिंह (तरलोक सिंह से पैदा हुए) ने मोती राम और रिखी राम को 23 दिसंबर, 1959 को 5,000 रुपये में बेच दी थी। इस बिक्री को तरलोक सिंह के नाबालिग बेटों बखवंत सिंह और मोहिंदर सिंह ने अपनी मां करम कौर, जो तरलोक सिंह की विधवा भी हैं, के माध्यम से 16 दिसंबर, 1960 को इस उद्देश्य के लिए दायर एक मुकदमे में छूट देने की मांग की थी। पूर्व-खालीदारों ने बेची गई जमीन के खतों में विक्रेताओं और बलकार सिंह और नछत्तर सिंह के भाइयों के साथ सह-हिस्सेदार के रूप में अपने अधिकार का दावा किया। पूर्व-खाली करने वालों ने दावा किया कि जमीन केवल 3,200 रुपये में बेची गई थी, जबकि बिक्री-पत्र में उल्लिखित कीमत 5,000 रुपये थी। यह उल्लेख किया जा सकता है कि मुकदमा, संभवतः असावधानी के कारण, खसरा नंबर 871 और 877 के बजाय 871 और 872 के संबंध में लाया गया था, जो बेचे गए थे।

ट्रायल कोर्ट ने पाया कि पूर्व-खालीकर्ता पहले आधार पर सफल होने के हकदार नहीं थे क्योंकि यह स्थापित नहीं किया गया था कि वे विवादित भूमि में सह-हिस्सेदार थे, हालाँकि, दूसरे आधार पर, ट्रायल कोर्ट ने वादी पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया और यह माना गया कि यद्यपि बलकार सिंह और नछत्तर सिंह के सौतेले भाई थे, फिर भी वे सभी पंजाब प्रीम्प्शन एक्ट के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उनके बराबर रैंक के हकदार थे। , जिसका मैं शीघ्र ही विज्ञापन करूंगा। परिणामस्वरूप, बेची गई जमीन के दो-तिहाई हिस्से के संबंध में पूर्व-खाली करने वालों के पक्ष में एक डिक्री दी गई, यह माना गया कि वे इंद कौर के बेटे नहीं होने के कारण उनके हिस्से को पहले से खाली नहीं कर सकते थे। ट्रायल कोर्ट का मानना था कि खसरा नंबर 877 के संबंध में कोई वैध मुकदमा नहीं लाया गया था, केवल खसरा नंबर 871 के तहत भूमि के लिए डिक्री पारित की जा सकती थी। तदनुसार मुकदमे को दो = टी< में डिक्री किया गया था। आनुपातिक पी. के भुगतान पर खसरा नंबर. एक \'मैं w~- रु.3,200 पाया गया।

इस डिक्री से प्री-एम्प्टर द्वारा अपील की गई थी, जबकि विक्रेताओं ने बाजार मूल्य और वादी के प्री-एम्प्ट के अधिकार को चुनौती देने के लिए क्रॉस-आपत्तियां दायर की थीं। 10 सितंबर, 1962 को निचली अपीलीय अदालत ने माना कि खसरा संख्या 877 का छूटना अनजाने में हुआ था और यदि मुकदमे का फैसला सुनाया जाना था तो उसने उस स्तर पर संशोधन की अनुमति दी होगी। लेकिन उनके विचार में मुकदमे का फैसला नहीं किया जा सका क्योंकि करमकौर का तरलोक सिंह के साथ विवाह साबित नहीं हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि जिला न्यायाधीश, बामला के समक्ष, अपील की सुनवाई करते हुए, प्री-एम्प्टर्स ने सह-स्वामित्व के आधार पर प्री-एम्प्शन के लिए अपने दावे पर जोर नहीं दिया। जिला न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि विवादित भूमि की वास्तविक कीमत 3,200 रुपये थी, न कि 5,000 रुपये। परिणामस्वरूप, प्रीएम्प्टर्स की अपील खारिज कर दी गई और प्रतिवादियों की क्रॉस-आपत्तियों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

मोती राम और अन्य बनाम बखवंत सिंह और अन्य (शमशेर बहादुर, जे.)

उच्च न्यायालय में आगे की अपील में, 12 मार्च, 1964 को महाजन, जे. ने एक अतिरिक्त मुद्दा तैयार किया और ट्रायल जज को यह निर्धारित करने की आवश्यकता थी कि "क्या वादी इंद कौर या करम कौर से तरलोक सिंह के बेटे हैं?" इस मुद्दे को तैयार करने वाले महाजन, जे. का इरादा इस सवाल को शामिल करने का था कि क्या करम कौर की वैध रूप से तरलोक सिंह से शादी हुई थी। विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश श्रीमती हरमोहिंदर कौर ने 16 जून, 1964 को रिपोर्ट दी कि करम कौर की वैध रूप से तरलोक सिंह से शादी हो गई थी, और 18 सितंबर, 1964 को महाजन, जे. ने अपील की अनुमति दी और इंड कौर के 5000 रुपये के भुगतान के हिस्से के संबंध में भी मुकदमे का फैसला सुनाया।

विद्वान न्यायाधीश ने 29 नवंबर, 1961 की स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जो न्यायालय के रिकॉर्ड का एक हिस्सा थी, जिसके अनुसार विवादित भूमि की कीमत 400 रुपये प्रति बीघा पाई गई। इंद कौर के हिस्से के संबंध में मुकदमे का फैसला करते समय महाजन, जे. ने नाथी सिंह बनाम लखमी चंद, आर.एस.ए. नंबर 1616, 1960 में गुरदेव सिंह, जे. के फैसले पर भरोसा किया, जिसका फैसला 20 मार्च, 1962 को हुआ था। बाद में जंगली और अन्य बनाम लख्मी चंद और अन्य (1) में दुलत और आर. पी. खोसला, जे जे द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील में इसकी पुष्टि की गई।

लेटर्स पेटेंट बेंच की राय में, ''पंजाब प्रीएम्प्शन एक्ट के तहत बेटों को जो अधिकार दिया गया है, वह 'सेल' को प्री-एम्प्ट करने का अधिकार है, न कि बिक्री का हिस्सा। इस प्रकार, सभी विक्रेताओं के प्रत्येक पुत्र अपने पूर्व-अधिकार के आधार पर बेची गई पूरी संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा करने का हकदार होगा।कोष्ठक में इसका उल्लेख किया जा सकता है कि महाजन, जे, ने लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत छुट्टी देने के लिए विक्रेता के वकील के अनुरोध को स्वीकार कर लिया क्योंकि नाथी के मामले में गुरदेव सिंह, जे का फैसला अपील का विषय था। मुख्य न्यायाधीश, फाल्शॉ और खन्ना, जे की लेटर्स पेटेंट बेंच के समक्ष, विक्रेताओं के वकील की यह दलील कि वादी विक्रेताओं के भाइयों के रूप में सफल होने के हकदार नहीं थे क्योंकि वे सौतेले भाई थे, को पक्षपात नहीं मिला और विद्वान मुख्य न्यायाधीश का पक्ष नहीं लिया गया। , जिनसे खन्ना, जे ने सहमति जताते हुए मामले के इस पहलू पर इस प्रकार टिप्पणी की:-

" . . किसी अधिकार के अभाव में भी, मुझे यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि इस संदर्भ में, जहां एक जमींदार के एक से अधिक पत्नियों से बेटे हैं, सभी बेटे 'दूसरी' पत्नी के लिए भाई हैं। और इसलिए, जहां तक बात उनके सौतेले भाइयों के दो-तिहाई शेयरों की है, वादी निश्चित रूप से बिक्री से पहले छूट दे सकते हैं।''

हालाँकि, मुख्य न्यायाधीश को नाथी सिंह के मामले में गुरदेव सिंह, जे. के निर्णय की शुद्धता और इसकी पुष्टि करने वाली लेटर्स पेटेंट बेंच के निर्णय की शुद्धता के बारे में संदेह था, उन्होंने सोचा कि इन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। बेंच ने आगे कहा कि यह तय करना कानून का एक कठिन प्रश्न है कि क्या 1964 के पंजाब अधिनियम संख्या 13 द्वारा पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट में पेश किए गए संशोधन ने इंद्र कौर के सौतेले बेटों को प्री-एम्प्शन का पूर्वव्यापी अधिकार दिया है? लेटर्स पेटेंट बेंच ने तदनुसार अपील को निपटान के लिए पूर्ण बेंच को भेज दिया। हमारे सामने, वह प्रश्न जिस पर मुख्य न्यायाधीश फाल्शॉ ने बेंच के सन्दर्भित आदेश में महसूस किया कि कोई कठिनाई नहीं है, उस पर भी जोरदार ढंग से चर्चा की गई है और इस बिंदु की सराहना करने के लिए, साथ ही वे प्रश्न भी जिन पर बेंच को कठिनाई का सामना करना पड़ा, 1960 और 1964 के अधिनियमों द्वारा संशोधित पंजाब प्रीमेम्पशन अधिनियम, 1913 के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करना आवश्यक है।

"15. (1) कृषि भूमि और गांव की अचल संपत्ति के संबंध में पूर्व-खाली का अधिकार निहित होगा-

(ए) जहां 1 बिक्री एकमात्र मालिक द्वारा होती है, -

सबसे पहले, विक्रेता के बेटे या बेटी या बेटे के बेटे या बेटी के बेटे में;

दूसरे, विक्रेता के भाई या भाई के बेटे में;

तीसरा, विक्रेता के पिता के भाई या पिता के भाई के पुत्र में;

मोद राम और अन्य बनाम -बखवंत सिंह और अन्य (शमशेर बहादुर, जे.)

चौथा, किरायेदार में जो विक्रेता की किरायेदारी के तहत बेची गई भूमि या संपत्ति या उसके हिस्से को रखता है;

(बी) जहां बिक्री संयुक्त भूमि या संपत्ति में से एक हिस्से की है और सभी सह-हिस्सेदारों द्वारा संयुक्त रूप से नहीं की जाती है, -

सबसे पहले, विक्रेता या विक्रेताओं के बेटों या बेटियों या बेटों के बेटों या बेटियों के बेटों में;

दूसरे, विक्रेता या विक्रेताओं के भाइयों या भाई के बेटों में;

तीसरा, विक्रेता या विक्रेताओं के पिता के भाइयों या पिता के भाई के पुत्रों में;

चौथा, अन्य सह-हिस्सेदारों में;

पांचवें, उन किरायेदारों में जो विक्रेता या विक्रेताओं की किरायेदारी के तहत बेची गई भूमि या संपत्ति या उसके हिस्से को रखते हैं;

(सी) जहां बिक्री संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली भूमि या संपत्ति की है और सभी सह-हिस्सेदारों द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है, -

सबसे पहले, विक्रेताओं के बेटों या बेटियों या बेटों के बेटों या बेटियों के बेटों में;

दूसरे, विक्रेताओं के भाइयों या भाई के बेटों में;

तीसरे, पिता के भाइयों या पिता के भाई के विक्रेताओं के पुत्रों में;

चौथा, उन किरायेदारों में जो विक्रेताओं या उनमें से किसी एक की किरायेदारी के तहत बेची गई जमीन या संपत्ति या उसका एक हिस्सा रखते हैं।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी-

(ए) जहां बिक्री उस महिला के पति या पत्नी द्वारा की जाती है, जिस पर वह अपने पिता या भाई के माध्यम से सफल हुई है या ऐसी भूमि या संपत्ति के संबंध में बिक्री विरासत के बाद ऐसी महिला के बेटे या बेटी द्वारा की जाती है, पूर्व-मुक्ति का अधिकार निहित होगा, -

(i) यदि बिक्री ऐसी महिला द्वारा उसके भाई या भाई के बेटे में की जाती है;

(ii) यदि बिक्री ऐसी महिला के बेटे या बेटी द्वारा की जाती है, तो विक्रेता या विक्रेता की मां के भाई या मां के भाई के बेटे;

(बी) जहां बिक्री भूमि या संपत्ति की एक महिला द्वारा की जाती है, जिसमें वह अपने पति के माध्यम से सफल हुई थी, या अपने बेटे के माध्यम से, यदि बेटे को अपने पिता से बेची गई भूमि या संपत्ति विरासत में मिली है, तो छूट का अधिकार निहित होगा,-

सबसे पहले, ऐसी महिला के बेटे या बेटी में;

"दूसरी बात, ऐसी महिला के पति के भाई या पति के भाई के बेटे में।"

पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट, 1964 (1964 का अधिनियम 13) द्वारा धारा 15 की उप-धारा (2) के खंड (बी) में पैराग्राफ 'प्रथम' अब इस प्रकार है: -

“सबसे पहले, महिला के ऐसे पति के बेटे या बेटी में”।

ध्यान देने योग्य मुख्य विशेषता यह है कि जबकि मुख्य अधिनियम में पूर्व-खाली अधिकार वंशावली वंशजों और गोत्रों को दिया जाता है, अधिनियम ने इस अधिकार को निकटतम संबंधों तक सीमित कर दिया है।किरायेदारों के लिए प्रीमेप्टिव अधिकार अधिनियम की एक नई विशेषता है और संयुक्त होल्डिंग्स की बिक्री के मामले में सह-हिस्सेदारों को भी अधिकार का आनंद मिलता है जब बिक्री संयुक्त भूमि या संपत्ति में से एक हिस्से की होती है और सभी सह-हिस्सेदारों द्वारा संयुक्त रूप से नहीं की जाती है। हालाँकि, हम वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के तहत भूमि की बिक्री से चिंतित हैं, यह बिक्री संयुक्त मालिकों इंद्र कौर, बलकार सिंह और नछत्तर सिंह द्वारा की गई है। वादी उप-धारा (1) के खंड (सी) के उप-खंड (दूसरे) के आधार पर पूर्व-खाली अधिकार का दावा करते हैं जिसके तहत ऐसा अधिकार विक्रेताओं के भाइयों या भाई के बेटों में निहित है। मुख्य न्यायाधीश फाल्शॉ ने, जो अनुच्छेद पहले ही उद्धृत किया जा चुका है, विचार किया है कि किसी अधिकार के अभाव में भी, एक भाई में सौतेला भाई भी शामिल है, और जहां तक संदर्भ देने वाली पीठ का संबंध है, मामला वहीं समाप्त हो गया।

हमारे सामने, विद्वान मोती राम और अन्य बनाम बखवंत सिंह और अन्य (शमशेर बहादुर, जे.) प्रतिशोधी अपीलकर्ताओं के वकील श्री दलीप चंद गुप्ता द्वारा बहुत दृढ़ता से आग्रह किया गया है कि विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सटीक नहीं है और अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के उप-खंड (दूसरे) के उद्देश्य और उद्देश्य के विरुद्ध है। यह पहली बार श्री गुप्ता द्वारा एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि प्री-एम्प्टर के पक्ष में कोई इक्विटी मौजूद नहीं है जिसका एकमात्र उद्देश्य एक क़ानून द्वारा बनाए गए अधिकारों के आधार पर एक वैध लेनदेन को परेशान करना है। उन्होंने राधाकिशन बनाम श्रीधर[1] पर भरोसा किया है, जिसमें न्यायालय के लिए श्री न्यायमूर्ति कपूर ने पृष्ठ 1372 पर इस प्रकार कहा था:-

[1] ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 1368.

"किसी भी वैध तरीके से प्री-एम्प्शन के कानून को पराजित करना विक्रेता या विक्रेता की ओर से धोखाधड़ी नहीं है और एक व्यक्ति सभी वैध तरीकों से प्री-एम्प्शन के कानून से दूर रहने का हकदार है....प्री-एम्प्शन का अधिकार एक कमजोर अधिकार है और इसे अदालतों द्वारा अनुकूल दृष्टि से नहीं देखा जाता है और इसलिए, कोर्ट प्री-एम्प्शनर की मदद करने के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं जा सकते हैं।

इस प्राधिकार से जो कुछ भी स्पष्ट किया जा सकता है वह यह है कि क़ानून में सन्निहित पूर्वव्यापी अधिकार को सख्ती से समझा जाना चाहिए और कोई भी न्यायालय इसके दायरे से परे जाने का हकदार नहीं है। इस निर्णय के फैसले के लिए, हमारी राय में, यह आवश्यक नहीं है कि क़ानून की भाषा को हर तरह से एक ऐसा निर्माण देने के लिए तनावपूर्ण किया जाए जो प्रतिशोध के अनुकूल हो और प्री-एम्प्टर के प्रतिकूल हो, जब उसने कहा कि न्यायालय प्री-एम्प्शनर की मदद करने के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं जाना है, न ही हम सर्वोच्च न्यायालय के प्राधिकार का यह अर्थ समझते हैं कि स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से दिए गए प्री-एम्प्शन के वैधानिक अधिकार पर अंकुश लगाया जाना चाहिए या मध्यम, पूर्व-मुक्ति का अधिकार स्वयं "कमजोर" है।

श्री गुप्ता ने गुलराज सिंह बनाम मोटा सिंह [2]में सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले के आधार पर कहा, जहां यह कहा गया था कि अधिनियम की धारा 15 (2) (बी) के तहत "बेटा या बेटी" का मतलब है "केवल महिला विक्रेता का वैध पुत्र या वैध पुत्री और इसमें नाजायज पुत्र या पुत्री शामिल नहीं होंगे", प्रस्तुत है कि तर्क की समानता पर उपधारा (1) के खंड (सी) के उप-खंड (दूसरे) में "भाई" शब्द में सौतेला या सौतेला भाई शामिल नहीं किया जाएगा। मेरा मानना है कि एक नाजायज़ बेटे या बेटी की स्थिति की तुलना सौतेले भाई या सौतेली बहन से नहीं की जा सकती। यह ध्यान में रखना होगा कि प्री-एम्प्शन के प्रतिबंधित अधिकार का प्राथमिक उद्देश्य विक्रेता के निकटतम रिश्तेदारों के बीच संपत्ति को बनाए रखना है और यह स्वीकार्य रूप से आग्रह नहीं किया जा सकता है कि इस उद्देश्य को नाजायज मुद्दों जैसे सौतेले भाइयों या सौतेली बहनों को छोड़कर बढ़ावा दिया जाएगा या पूरा किया जाएगा। यह हम पर बहुत ही जबरदस्ती थोपा गया है कि इस अधिनियम में भावी पूर्ववर्तियों की सूची में भारी कटौती की गई है और विधानमंडल का उद्देश्य सौतेले भाई को "भाई" के रूप में शामिल करने से बचना था, जो इसके सख्त अर्थ में है। और वकील के विचार में सामान्य अर्थ, पूर्ण रक्त के भाई तक ही सीमित होना चाहिए। हम तुरंत कह सकते हैं कि "भाई" शब्द का विस्तारित अर्थ ऐसे किसी भी उद्देश्य को विफल करने के लिए नहीं बनाया गया है, खासकर जब धारा 15 की उपधारा 1 के खंड (ई) के उप-खंड (तीसरे) के तहत पूर्व-खाली अधिकार दिया गया है -विक्रेता के पिता के भाई के बेटे जैसे व्यक्ति के लिए जो रिश्ते में सौतेले भाई से दूर है।

[2] ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 608

बाउवियर लॉ डिक्शनरी (1914 संस्करण), खंड । में "ब्रदर" को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है "जो एक ही पिता और माता से दूसरे के साथ या उनमें से केवल एक से पैदा हुआ है। जब भाई एक ही पिता और माता से पैदा होते हैं तो वे पूर्ण रक्त के होते हैं, और जब वे उनमें से केवल एक से उत्पन्न होते हैं तो आधे रक्त के होते हैं। जब वे एक ही पिता और माता की संतान होते हैं, तो उन्हें ब्रदर्स जर्मेन कहा जाता है; जब वे एक ही पिता से आते हैं लेकिन एक ही मां से नहीं, तो वे सजातीय भाई होते हैं; जब वे एक ही माँ के बच्चे होते हैं, लेकिन एक ही पिता के नहीं, तो वे सहोदर भाई होते हैं। सौतेला भाई वह होता है जो एक ही पिता या माता से पैदा होता है, लेकिन दोनों से नहीं। . ." कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम (1938 संस्करण) खंड XII में, "भाई" को "एक ऐसे पुरुष व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक ही पिता और माता हैं, या जिनके पास उनमें से एक है;" वह जो एक ही पिता और माता से दूसरे के साथ, या उनमें से केवल एक से पैदा हुआ हो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम में, यह कहा गया है कि जब इस शब्द का उपयोग बिना किसी योग्य शब्द के किया जाता है, तो इसमें आधे-रक्त का भाई भी शामिल हो सकता है। स्ट्राउड के न्यायिक शब्दकोश (तीसरे संस्करण) खंड में, यह कहा गया है कि विवाह अधिनियम, 1949 के तहत "भाई में सौतेले भाई को शामिल किया जाएगा"। स्ट्राउड के अनुसार, भाइयों और बहनों को दिए जाने वाले उपहार में आधा खून शामिल होता है और इसी तरह रिश्ते के अन्य सभी स्तरों के संबंध में भी। हेल्सबरी के इंग्लैंड के कानून (तीसरा संस्करण) खंड 19, पृष्ठ 782 पर, विवाह अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों का हवाला देते हुए दिखाया गया है कि एक पुरुष, अन्य बातों के अलावा, अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता है और एक महिला अपने भाई से शादी नहीं कर सकती है और 'भाई' और 'बहन' दोनों अभिव्यक्तियों में सौतेले भाई और बहन शामिल हैं।

मोती राम और अन्य बनाम बखवंत सिंह और अन्य (शमशेर बहादुर, जे.) शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी (1961 संस्करण) खंड । के अनुसार, "पुरुष एक ही माता-पिता या माता-पिता की संतान के रूप में दूसरों (पुरुष या महिला) से संबंधित है बाद वाले मामले में, उसे अधिक उचित रूप से सौतेला भाई, या आधे खून का भाई कहा जाता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 27 कहती है कि-

"उत्तराधिकार के प्रयोजन के लिए, कोई भेद नहीं है-

(ए) उन लोगों के बीच जो किसी मृत व्यक्ति से उसके पिता के माध्यम से संबंधित हैं, और जो लोग उसकी मां के माध्यम से उससे संबंधित हैं; या

(बी) उन लोगों के बीच जो किसी मृत व्यक्ति से पूर्ण रक्त से संबंधित हैं, और जो उससे आधे रक्त से संबंधित हैं; या

(सी) । . . ”

मुल्ला के हिंदू कानून (13वां संस्करण) पृष्ठ एचएल के अनुसार, विरासत के मामले में एकमात्र अंतर यह है कि पूर्ण रक्त के भाई आधे रक्त के भाइयों से पहले सफल होते हैं।

प्री-एम्प्शन के क़ानून में भाई और सौतेले भाई के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है, लेकिन श्री गुप्ता ने तर्क दिया है कि इस अधिनियम ने प्री-एम्प्शन के पात्र व्यक्तियों की संख्या में भारी कमी ला दी है, यह यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि सौतेले भाइयों को अधिकार का प्रयोग करने से बाहर रखा जाएगा। जब भी एक भाई और सौतेले भाई के बीच अंतर करने की मांग की जाती है, तो इसे इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाता है, अन्यथा "भाई" में "सौतेला भाई" भी शामिल होता है जो या तो सजातीय या गर्भाशय संबंधी हो सकता है। विधायिका पूर्ण रक्त, अर्ध रक्त और गर्भाशय के भाइयों के लिए पूरी तरह से जीवित रही है। वास्तव में, इन शर्तों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ई) में अलग से परिभाषित किया गया है। जैसा कि उत्तराधिकार के कानून में है, प्री-एम्प्शन एक्ट के तहत खरीद के लिए अधिकार प्रदान करना उस व्यक्ति के साथ विक्रेता के रिश्ते की डिग्री पर आधारित है, जिसे अधिकार दिया गया है, सजातीयता परीक्षण है। यदि पूर्व-मुक्ति का अधिकार केवल पूर्ण भाइयों तक ही सीमित रखने का इरादा था, तो प्रतिबंध को विशेष रूप से नोट किया गया होता और, जैसा कि हमने पहले देखा, जब पिता के भाई के बेटे को अधिकार दिया गया है, तो कोई कल्पनीय कारण नहीं है कि सौतेला भाई क्यों जो सजातीयता में निकटतम है, उसे बाहर रखा जाना चाहिए।इस तरह के अधिकार को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पूर्व-उत्पत्ति का अधिकार समुद्री डाकू है या यह अनुबंध की पवित्रता को परेशान करता है और अनुबंध करने की स्वतंत्रता के अधिकार को नष्ट कर देता है। प्री-एम्प्टिव अधिकार को मान्यता दी गई है और एक विशेष रिश्तेदार जो अन्यथा प्री-एम्प्टिव के लिए पात्र है, उसे केवल इस कारण से इस लाभ से बाहर नहीं किया जा सकता है कि पूर्ण रक्त के भाई के पास उत्तराधिकार के मामले में आधे रक्त के भाई की तुलना में बेहतर अधिकार है। हमारे विचार में, समस्या का सही परिप्रेक्ष्य यह है कि सौतेला भाई वह भाई होता है जिसे विधायिका द्वारा उसके पूर्व-मुक्ति के अधिकार का प्रयोग करने से बाहर नहीं रखा गया है।

श्री गुप्ता ने सुरजन सिंह बनाम हरचरण सिंह[3] में महाजन और नरूला जेजे के हालिया डिवीजन बेंच के फैसले को हमारे ध्यान में लाया है, जहां यह माना गया है कि धारा 15 (एल) (ए) में "भाई" शब्द दूसरे इसका तात्पर्य "सगे भाई" से है न कि "सौतेले भाई" या "गर्भवती भाई" से।बेंच एकमात्र मालिक द्वारा बिक्री के मामले पर विचार कर रही थी और निस्संदेह उप-खंड (दूसरे) में "भाई" शब्द पर रखा गया निर्माण उपधारा 15 के खंड (सी) के उप-खंड (दूसरे) पर यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होगा। जिससे हम वर्तमान मामले में चिंतित हैं। महाजन जे, जिनसे नरूला जे सहमत थे, ने माना कि धारा 15 के संदर्भ में "भाई" शब्द एक सगे भाई को दर्शाता है, न कि सौतेले भाई या गर्भाशय भाई को, इसका कारण यह है कि प्रीएम्प्शन का कानून एक समुद्री कानून है और सख्ती से समझा जाना चाहिए |विद्वान न्यायाधीश के विचार में, "यदि दो व्याख्याएं संभव हैं, तो उस व्याख्या को प्राथमिकता

[3] 1967 वर्ष. एल.जे. (पीबी. एवं एचआर.) 275.

दी जानी चाहिए, जो इसके संचालन को प्रतिबंधित करती है, उस व्याख्या के बजाय जो इसके संचालन को व्यापक बनाती है।" महाजन जे. ने बाउवियर्स लॉ डिक्शनरी में परिभाषा के बाद के भाग पर भी भरोसा किया, जिसका उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूं। महाजन जे. इसके अलावा इस विचार से भी प्रभावित थे कि "भारतीय मानस के लिए 'भाई' शब्द आम तौर पर एक सगे भाई को इंगित करता है, हालाँकि इस शब्द का इस्तेमाल रिश्ते के लिए भी किया गया है, चाहे वह सौतेले भाई का हो या सौतेले भाई का।" फैसले में विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि निष्कर्ष "पहली धारणा" पर आधारित था क्योंकि इसमें एक ऐसा प्रश्न शामिल था जो अधिकारहीन था।

विद्वान न्यायाधीशों का बहुत सम्मान करते हुए, हम उन कारणों से सहमत होने में असमर्थ हैं, जिन्होंने पीठ को सौतेले भाई को प्री-एम्प्शन के अधिकार के लाभ से बाहर करने के पक्ष में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर किया। "भाई" में न्यायशास्त्र की सभी प्रणालियों में 'सौतेला भाई' शामिल है जिसके बारे में हम जानते हैं और एक विपरीत इरादे को स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। हम यह नहीं देखते हैं कि एक सौतेले भाई का बहिष्कार मात्र प्री-एम्प्शन के कानून पर स्वीकृत वस्तुओं और प्रतिबंधों को कैसे आगे बढ़ाएगा, जिसे एक समुद्री अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। जहां क़ानून ने एक भाई को और वास्तव में सौतेले भाई की तुलना में अधिक दूर के संबंधों को सुरक्षा दी है, हमें यह सोचने के लिए राजी नहीं किया जा सकता है कि सौतेला भाई बहिष्कार का उद्देश्य था। वास्तव में, हम इस विचार से सहमत हैं कि यदि ऐसी कोई वस्तु थी तो इसके लिए विशेष रूप से प्रावधान किया जाना चाहिए था। न ही हम इस तर्क को स्वीकार करने का अपना रास्ता देखते हैं कि दो व्याख्याएं होने के कारण, जो पूर्व-मुक्ति के अधिकार को प्रतिबंधित करने के पक्ष में है, उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो इसे व्यापक बनाती है। एक श्रेणी के रूप में "भाई" को पूर्व-खाली का अधिकार दिया गया है और हम यह नहीं देखते हैं कि दो व्याख्याएँ कैसे संभव हैं और परिणामस्वरूप एक को दूसरे पर वरीयता देने का सवाल ही नहीं उठता।

यह उल्लेख करना शेष है कि सुरजन सिंह के मामले में, महाजन जे ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए, दो निर्णयों का संदर्भ दिया था, एक सुप्रीम कोर्ट के गुलराज बनाम मोटा सिंह (3) का, जिसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, और वजागर सिंह बनाम रतन सिंह[4] के अन्य मामले में, जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने स्वयं अकेले बैठकर यह निर्णय दिया था कि पिचलाग पुत्र को अपनी मां द्वारा की गई भूमि की बिक्री से पहले छूट देने का कोई अधिकार नहीं था, जहां भूमि उसे अपने पति से विरासत में मिली थी, जो प्री-एम्प्टर का पिता नहीं था। मुझे लगता है कि पिचलाग बेटे का मामला एक ही पिता के बेटे से काफी अलग है, उसका सजातीयता के आधार पर कोई दावा नहीं है।

[4] 1965 पी.यू. 258

श्री गुप्ता द्वारा लिया गया अगला बिंदु यह है कि भले ही बिक्री सौतेले भाइयों के कहने पर पूर्व-खाली योग्य हो, लेकिन कम से कम इंद कौर का हिस्सा पूर्व-खाली नहीं था। पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट, 1913 की धारा 13 पर भरोसा रखा गया है, जिसके अनुसार: -

"जब भी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्व-मुक्ति का अधिकार किसी वर्ग या व्यक्तियों के समूह में निहित होता है, तो अधिकार का प्रयोग ऐसे वर्ग या समूह के सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा सकता है और यदि उन सभी द्वारा संयुक्त रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उनमें से किन्हीं दो या अधिक द्वारा संयुक्त रूप से प्रयोग किया जा सकता है और यदि उनमें से किन्हीं दो या अधिक द्वारा संयुक्त रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है।"

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सफल होने के लिए प्री-एम्प्टर को विक्रेता के साथ अपना संबंध स्थापित करना होगा और प्रत्येक विक्रेता के साथ संयुक्त बिक्री के मामले में। सवाल यह है कि क्या प्री-एम्प्टर रिलेहोन-शिप के आधार पर बेची गई पूरी संपत्ति पर दावा कर सकता है, जब यह पाया जाता है कि वह एक या अधिक विक्रेताओं से संबंधित नहीं है? नाथी सिंह बनाम लखमी चंद, आर.एस.ए. संख्या 1616/1960 में, 20 मार्च 1962 को फैसला सुनाया गया। गुरदेव सिंह जे का विचार था कि पूर्व-मुक्ति का उद्देश्य बिक्री था। भले ही कुछ विक्रेताओं के साथ संबंध स्थापित नहीं किया गया हो, फिर भी संपूर्ण लेनदेन को रोका जा सकता है। इस मामले में सोहन लाल और उनके भतीजे (भाई के बेटे) खिल्लू और फकीरिया ने अपनी कृषि भूमि की संयुक्त हिस्सेदारी नाथी सिंह और अन्य को बेच दी थी। खिल्लू के पुत्र किरणपाल और फकीरिया के पुत्र लख्मी चंद ने विक्रेताओं के साथ संबंध के आधार पर पूर्व-मुक्ति के अधिकार का दावा करते हुए अग्रिम छूट के लिए एक मुकदमा लाया। निचली अपीलीय अदालत द्वारा अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के तहत वादी के पक्ष में मामला तय किया गया था, लेकिन किरणपाल और लखमी चंद को केवल अपने संबंधित पिता के शेयरों को छूट देने का हकदार माना गया था। 5/8वें हिस्से के संबंध में एक डिक्री पारित की गई, शेष 3/8वां हिस्सा सोहन लाल का था, जिसका हिस्सा पूर्व-खालीकर्ता रिश्ते के आधार पर दावा नहीं कर सकते थे। गुरदेव सिंह जे ने प्री-एम्पॉटर्स की अपील की अनुमति दी और सोहन लाल के हिस्से सहित पूरी संपत्ति के लिए मुकदमे का फैसला इस आधार पर किया कि प्रत्येक वादी पूरी बिक्री को प्री-इमोट करने का हकदार था। इस डिक्री की पुष्टि जंगली बनाम लख्मी चंद (1) में दुलत और आर. पी. खोसला जे.जे. द्वारा की गई थी। यह इस निर्णय का निर्णय है जिसकी शुद्धता पर संदर्भित बेंच द्वारा संदेह किया गया है क्योंकि एलिस के ग्रंथ तेल प्री-एम्प्शन के कानून में बताए गए कुछ पूर्व निर्णयों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

यह प्रस्ताव कि प्री-एम्प्शन का अधिकार आम तौर पर प्री-एम्प्शनर के अधिकार की सीमा तक सीमित है, चुनौती के लिए खुला नहीं है। इस सिद्धांत से जो निकलता है वह यह है कि एक प्री-एम्प्टर संपूर्ण दावा करने के लिए बाध्य नहीं है जब उसका प्री-एम्प्शन का अधिकार केवल एक हिस्से

तक फैला हुआ है। पंजाब चीफ कोर्ट की फुल बेंच का फैसला है| सांवल दास बनाम गुर पार शाद[5] जहां छह न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा कि जब दो घर जो एक-दूसरे से सटे हुए हैं, संयुक्त रूप से बेचे जाते हैं, तो उस घर के मालिक का प्री-एम्प्शन का अधिकार जो दोनों घरों में से केवल एक से जुड़ा हुआ है बेचा गया मामला केवल उस एक घर तक ही सीमित है, बेचे गए दोनों घरों तक नहीं। आसपास के घरों का मालिक केवल उस घर के संबंध में प्री-एम्प्शन का दावा कर सकता है जिस पर उसका अधिकार फैला हुआ है। उत्तम चंद बनाम लाहौरी मल [6] के एक अन्य डिविजन बेंच मामले में, यह माना गया था कि "एक व्यक्ति द्वारा अलग-अलग संपत्तियों का सौदा, जिसके पास ऐसे सौदे के केवल एक हिस्से पर अधिमान्य अधिकार है, उसे एक साथ खरीदे गए अन्य हिस्से के संबंध में छूट का अधिकार नहीं देता है" |यह निःसंदेह सत्य है कि ऋण देने वाले को सौदे को उसकी संपूर्णता में लेना होता है, टुकड़ों में नहीं। इस सिद्धांत से कि एक प्री-एम्प्शनर पूरे सौदे का दावा करने के लिए बाध्य नहीं है, जब उसकी प्री-एम्प्शन का जोखिम केवल बेची गई संपत्ति के एक हिस्से तक ही विस्तारित होता है, एक और प्रस्ताव निकलता है कि एक प्री-एम्प्टर इसका हकदार नहीं है जितना उसका अधिकार है उससे अधिक का दावा करता है।

राम राखा मल बनाम देवी दास और अन्य [7] में चटर्जी और जॉनस्टोन जेजे द्वारा निर्णय लिया गया था, यह माना गया था कि "जहां एक सौदे में कई अलग-अलग संपत्तियां शामिल थीं और पूर्व-खालीकर्ता का खरीद का अधिमान्य अधिकार केवल ऐसे सौदे के एक हिस्से तक ही विस्तारित था|प्रीमेप्टर पूरा सौदा लेने का हकदार नहीं था, बल्कि केवल वह हिस्सा लेने का हकदार था जिस पर उसका बेहतर अधिकार था। दुल्ला बनाम हरिकिशन दास [8] में, जो जॉनस्टोन और शादी लाल जे जे का फैसला है, यह माना गया था कि "जहां एक बिक्री, जिसके संबंध में प्री-एम्प्शन का मुकदमा लाया गया है, दो विक्रेताओं द्वारा की जाती है और कुछ दृष्टिकोणों से अविभाज्य क्योंकि इसमें प्रत्येक विक्रेता को भुगतान की गई खरीद राशि की राशि नहीं बताई गई है, इसके बावजूद विक्रेता बेची गई संपत्ति के उस हिस्से को बनाए रखने का हकदार है जिसके संबंध में उसके अधिकार प्री-एम्प्टर के बराबर हैं "। डिवीजन बेंच ने कई फैसलों पर भरोसा किया और दुल्ला बनाम हरिकिशन दास (9) के अनुपात निर्णय पर किसी भी समय असहमति नहीं व्यक्त की गई। इस सिद्धांत को लाहौर उच्च न्यायालय ने गुलाम कादिर बनाम दित्ता [9]के पूर्ण पीठ के फैसले में भी मान्यता दी है, जहां यह कहा गया है कि "एक प्री-एम्प्टर को हमेशा उस अधिकतम का दावा करना चाहिए जिसका वह हकदार है या है एक श्रेष्ठ उपाधि और ऐसा करने में उसकी विफलता के परिणामस्वरूप उसका दावा इस आधार पर खारिज कर दिया जाएगा कि वह आंशिक छूट के लिए मुकदमा कर रहा था। एकमात्र असंगत

[5] 90 आरआरटी1909

[6] 112 पी.आर. 1907, ,

[7] 89 पी.आर.1905

[8] 6 पी.आर.1915

[9] 1945 पी.एल.आर. 224 (एफ.बी.)

टिप्पणी वारियम बनाम देसु, 1886 के 64 पंजाब रिकॉर्ड में रिपोर्ट किए गए मुख्य न्यायालय के एक पुराने फैसले में की गई थी, लेकिन बाद के फैसले में इस पर असहमति जताई गई थी, जिसका संदर्भ दिया गया है। पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट, 1913 की धारा 13 की भाषा हमेशा एक जैसी रही है और ऐसा लगता है कि जंगली बनाम लख्मी चंद (1) में दुलत और आर. पी. खोसला जे जे की बेंच ने यह विचार किया कि संयुक्त रूप से बिक्री मालिक पूरी तरह से प्री-एम्प्टेबल थे, भले ही वादी-प्री-एम्प्टर ने कुछ सह-विक्रेताओं के साथ संबंध स्थापित किए हों, पहले के निर्णयों को ध्यान में नहीं रखा था। पंजाब प्रीएम्प्शन एक्ट, 1913 की धारा 13 का हमेशा यह अर्थ लगाया गया है कि प्री-एम्प्टर संयुक्त बिक्री के मामले में विक्रेता या विक्रेताओं के हिस्से को प्री-एमोट करने का हकदार है, जिसके माध्यम से वह अपने अधिकार का दावा करता है। हमें ऐसा लगता है कि जंगली के मामले में निर्णय स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण सही ढंग से निर्णय नहीं लिया गया है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि मामले के अन्य पहलुओं पर हमने जो विचार किया है, उसमें वास्तव में जंगली के मामले में निर्णय की शुद्धता के बारे में प्रश्न में जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन जैसा कि संदर्भ देने वाली पीठ के विचार में है। मामले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, हम इस पहलू पर भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं।

इस अपील में उठाया गया तीसरा निवेदन यह है कि क्या अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के पैराग्राफ (प्रथम) के तहत वादी द्वारा इंद कौर का हिस्सा पूर्व-खाली किया जा सकता है। माना जाता है कि इंद कौर द्वारा की गई बिक्री उपधारा (2) द्वारा शासित होगी जो महिला द्वारा भूमि या संपत्ति की बिक्री से संबंधित है जिसमें वह अपने पिता, पति, पुत्र या भाई के माध्यम से सफल हुई है। यह सामान्य आधार है कि इंद कौर के हिस्से की बिक्री उस संपत्ति के संबंध में थी जिसमें वह अपने पति के माध्यम से सफल हुई थी और परिणामस्वरूप यह मामला इस उप-धारा के खंड (बी) द्वारा शासित होता है। ऐसी स्थिति में प्री-एम्प्शन का अधिकार ऐसी महिला के बेटे या बेटी में निहित होता है। उत्तरदाताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि प्री-एम्प्टमेंट के अधिकार का दावा करने वाले बेटे या बेटी को महिला विक्रेता के गर्भ से पैदा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा दावेदार, हालांकि उसका अपना मुद्दा नहीं है, फिर भी वह उस संपत्ति के संबंध में प्रीएम्प्शन का दावा करने का हकदार होगा, जो विक्रेता द्वारा ऐसे पति से आम सहमति के आधार पर विकसित की गई है। इस तर्क के लिए पैराग्राफ (दूसरा) से समर्थन मांगा गया है जो महिला के पति के भाई या पति के भाई के बेटे को अधिकार देता है। यह तर्क दिया जाता है कि यदि पति के भाई या इंद कौर के पति के भाई के बेटे को अधिकार था, तो यह शायद ही कल्पना की जा सकती है कि विधायिका एक अलग पत्नी से उसके पति के बेटे को पूर्व-मुक्ति के अधिकार का दावा करने से वंचित कर देती। इस संदर्भ में, यह बताया गया है कि 1964 के पंजाब अधिनियम 13 द्वारा "ऐसी" और 'महिला' के बीच "पति" शब्द जोड़कर पेश किए गए संशोधन ने केवल यह स्पष्ट किया कि स्पष्ट रूप से क्या इरादा था, हालांकि अधिनियम में ऐसा व्यक्त नहीं किया गया है। अपीलकर्ताओं की ओर से श्री गुप्ता ने बताया कि प्री-एम्प्शन का सुस्थापित सिद्धांत, जैसा कि हाल ही में सुंदर सिंह बनाम

नारायण सिंह [10] में सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य द्वारा दोहराया गया है, "प्री-एम्प्शनर" बिक्री की तारीख पर, मुकदमे की तारीख पर और डिक्री की तारीख पर अंतिम छूट का अधिकार होना चाहिए। यह उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि बिक्री की तारीख, जो 23 दिसंबर को हुई थी। 1959 इंद कौर के हिस्से के संबंध में निवेदकों को छूट का अधिकार था क्योंकि असंशोधित कानून के तहत वादी तरलोक सिंह की संपत्ति के उत्तराधिकार की कतार में थे। हालाँकि, यह 16 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया है। 1960, जब मुकदमा दायर किया गया था। संशोधित अधिनियम आधिकारिक में प्रकाशित होने के बाद लागू हो गया था|

4 फरवरी, 1960 को राजपत्र। संशोधन के तहत, विद्वान वकील की प्रस्तुति के अनुसार, प्री-एम्प्शन का अधिकार उन प्री-एम्प्टिशन में नहीं है, जो पैराग्राफ (प्रथम) के तहत इंद कौर के बेटे नहीं हैं। धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (बी) का। इसी तरह, जब 31 जनवरी, 1962 को ट्रायल कोर्ट का फैसला पारित किया गया, तो वादी उसी विकलांगता से पीड़ित था। चानन सिंह बनाम जय कौर, आर.एस.ए., क्रमांक 345/1960, 26 अक्टूबर, 1960 को दिए गए पंडित जे. के फैसले पर इस प्रस्ताव पर भरोसा किया गया है कि पैराग्राफ में विचार किया गया बेटा उस महिला का जन्म होना चाहिए। पंडित जे., इस फैसले में, एक बेटी के मामले से निपट रहे थे और उनके विचार में, "इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि प्रीम्प्टर का जन्म उसके गर्भ से हुआ होगा, और यह केवल तभी है कि वह उनकी बेटी कहा जा सकता है"। यथोचित परिवर्तनों के साथ वही तर्क बेटों के मामले में भी लागू होगा जो वादी दावा करते हैं। हालाँकि इस निर्णय के सिद्धांत की पुष्टि एल.पी.ए. में दुलत और आर-पी. खोसला जे.जे. की लेटर्स पेटेंट बेंच द्वारा की गई थी। 1961 का क्रमांक 91, 10 मई 1965 को निर्णय दिया गया, अपील को 1964 के पंजाब अधिनियम 13 द्वारा पेश किए गए संशोधन के कारण अनुमति दी गई थी, बेंच ने पाया कि वादी जय कौर ने संशोधित व्यक्तियों के विवरण का उत्तर दिया है खंड जो "महिला के ऐसे पति के बेटे या बेटी में" अधिकार निहित करता है। श्री सचदेवा की दलील में, संशोधन अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना चाहिए और जब यह अधिनियम 4 फरवरी, 1960 को लागू हुआ तो इसे क़ानून की किताब में शामिल माना जाना चाहिए। पृष्ठ 204 पर मैक्सवेल ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स (ग्यारहवें संस्करण) में वर्णित पूर्वव्यापी संचालन के निम्नलिखित सिद्धांत: -

"यह अंग्रेजी कानून का एक मौलिक नियम है कि किसी भी क़ानून को पूर्वव्यापी संचालन के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसा निर्माण अधिनियम की शर्तों में बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होता है, या आवश्यक और विशिष्ट निहितार्थ से उत्पन्न नहीं होता है।"

यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि 1964 के पंजाब अधिनियम 13 के पूर्वव्यापी संचालन के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन इसे आवश्यक और विशिष्ट निहितार्थ से समझा जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि 1964 का पंजाब अधिनियम 13 एक उपचारात्मक या उपचारात्मक अधिनियम है, जैसा कि इसके उद्देश्यों और कारणों से स्पष्ट है, जिसके बारे में मैं शीघ्र ही बताऊंगा।

---

[10] ए.टी.आर. 1966 एस.सी. 1977

उपचारात्मक अधिनियम पूर्व कानून में दोषों को ठीक करने के लिए पारित एक क़ानून है और यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि "ऐसी महिला के बेटे या बेटी में" शब्द कुछ अनिश्चितता के लिए सक्षम थे, इसलिए "के पति" शब्द को "शब्दों के बीच डाला गया था" ऐसे" और "महिला"। इस तर्क में निःसंदेह बल और तार्किकता है।

वकील के अनुसार, एक उपचारात्मक या उपचारात्मक अधिनियम में पूर्वव्यापी या पूर्वप्रभावी कार्रवाई होती है और उन्होंने पृष्ठ 243 पर सॉथरलैंड ऑन स्टैच्युटरी कंस्ट्रक्शन (तीसरा संस्करण) खंड 2 में निहित कानून के निम्नलिखित कथन पर भरोसा किया है: -

“हालाँकि, धारणा यह है कि सभी कानून केवल और केवल तभी संभावित रूप से संचालित होते हैं जब विधायिका ने स्पष्ट रूप से अपने इरादे का संकेत दिया है कि कानून पूर्वप्रभावी रूप से संचालित होगा और अदालतें इसे लागू करेंगी। पूर्वव्यापी कार्रवाई को ऐसे कानून के लिए अधिक आसानी से जिम्मेदार ठहराया जाएगा जो उपचारात्मक या वैधीकरण करने वाला है, न कि ऐसे कानून के लिए जो नुकसानदायक हो सकता है, हालांकि कानूनी रूप से, पिछले संबंधों और लेनदेन को प्रभावित कर सकता है।

इससे पहले, इसी ग्रंथ के पृष्ठ 135 पर कहा गया है: -

"जहां क़ानून अधिकारों को प्रभावित करता है या प्रकृति में उपचारात्मक है, इसे पूर्वव्यापी रूप से समझा जाएगा यदि विधायी इरादा स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पूर्वव्यापी संचालन का इरादा है।"

1964 के पंजाब अधिनियम संख्या 13 द्वारा प्रस्तुत संशोधन से पहले धारा 15 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के पैराग्राफ (प्रथम) और (द्वितीय) का बारीकी से विश्लेषण यह प्रदर्शित करेगा कि पति का एक बेटा एक महिला विक्रेता, हालांकि उसके गर्भ से पैदा नहीं हुई है, प्री-एम्प्शन की हकदार होगी, खासकर जब पति के भाई और यहां तक कि उस महिला के पति के भाई के बेटे को भी प्री-एम्प्शन का अधिकार दिया गया हो। दोहराने के लिए, प्री-एम्प्शन का अधिकार स्पष्ट रूप से सजातीयता के सिद्धांत पर दिया गया है, महिला विक्रेता की संपत्ति उसके पति की है, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि सौतेले बेटे को बाहर रखा जाए और पति के भतीजे को शामिल किया जाए। . केवल इससे यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि विधायिका ने सौतेले बेटे को शामिल करने का इरादा किया था और परिणामस्वरूप संशोधन अधिनियम को पूर्वव्यापी संचालन देना पड़ा क्योंकि ऐसा निर्माण अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य के अनुरूप और सद्भाव में प्रतीत होता है। विधेयक में जोड़े गए उद्देश्यों और कारणों के विवरण में इसका उल्लेख किया गया है जो अंततः 1964 का पंजाब अधिनियम 13 बन गया: -

“ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब प्री-एम्पशन/संशोधन) अधिनियम, 1960 (1960 का पंजाब अधिनियम संख्या 10) की धारा 15 (2) को लागू करने में विधायिका का इरादा पति की संतानों को प्री-एम्प्शन का अधिकार प्रदान करना था। और उस संपत्ति के संबंध में जिसके लिए एक महिला ऐसे पति के माध्यम से सफल हुई थी।

परन्तु धारा 15(2) के खण्ड (बी) में प्रयुक्त शब्दों से यह आशय स्पष्ट नहीं है। प्रावधान में एक और दोष यह है कि एक ही पति की दूसरी पत्नी से होने वाली संतानों को मौजूदा प्रावधानों में इस्तेमाल किए गए शब्दों से बाहर रखा गया है, जिससे ऐसा लगता है कि यह अनजाने में हुआ है।''

विधेयक में प्रयुक्त भाषा, जो कि "एक निजी सदस्य का विधेयक" था, पर उचित ध्यान देते हुए यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि संशोधन अधिनियम को पारित करने का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि पहले हमेशा क्या इरादा था। यह सच है कि वस्तुओं और कारणों का विवरण क़ानून के वास्तविक प्रावधानों के सही अर्थ और प्रभाव को समझने में एक स्वीकार्य सहायता नहीं है, जैसा कि मुख्य न्यायाधीश सिन्हा ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ [11] में देखा था, लेकिन ऐसा बयान, जैसा कि श्री न्यायमूर्ति शाह ने गुजरात विश्वविद्यालय बनाम श्री कृष्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले में देखा था, [12] "अक्सर उन कारणों का पता लगाने में मूल्यवान ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत कर सकते हैं जिन्होंने विधानमंडल को एक क़ानून बनाने के लिए प्रेरित किया" ।" दूसरे शब्दों में, वस्तुओं और कारणों का विवरण हालांकि इसे किसी क़ानून की व्याख्या के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, फिर भी यह हमें कानून का कारण निर्धारित करने में सक्षम बना सकता है। इस प्रकाश में देखने पर, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उद्देश्यों और कारणों का विवरण कम से कम यह स्पष्ट करता है कि धारा 15 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के पैराग्राफ (प्रथम) और संशोधन में एक खामी मौजूद थी। आईएनजी अधिनियम का उद्देश्य उस दोष को ठीक करना या सुधारना था। यह सिद्धांत कि महिला विक्रेता के गर्भ से बेटा या बेटी का जन्म होना चाहिए, 'पिचलाग' मुद्दे के रूप में टिकाऊ नहीं है, हालांकि उसके गर्भ से पैदा हुआ बच्चा योग्य प्री-एम्प्टर नहीं है, जैसा कि उइगर सिंह बनाम रतन सिंह में महाजन जे ने माना था। (5) और इसी सिद्धांत को चानन सिनाह बनाम जय कौर मामले में पंडित जे. द्वारा भी स्वीकार किया गया है। 1960 का आर.एस.ए. नंबर 345। इस तरह की गलतफहमी की संभावना को उद्देश्यों और कारणों में विधेयक का मुख्य उद्देश्य बताया गया है, जिसकी परिणति 1964 के पंजाब संशोधन अधिनियम 13 में हुई।

अपने निष्कर्षों को एक साथ जोड़ते हुए, हम मानते हैं कि "भाई" शब्द में प्री-एम्प्शन के कानून के संदर्भ में सौतेला या सौतेला भाई शामिल है और सुरजन सिंह बनाम हरचरण सिंह (4) का सही निर्णय नहीं लिया गया है। हमारा यह भी मानना है कि इंद कौर का हिस्सा अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के पहले पैराग्राफ के तहत छूट योग्य था और 1964 के पंजाब अधिनियम 13 द्वारा पेश किए गए संशोधन ने स्पष्ट कर दिया है कि क्या हो सकता है पहले कुछ हद तक अनिश्चित या अस्पष्ट रहे हैं और मामले की परिस्थितियों में संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना है।

---

[11] ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 1241

[12] ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 703

अंततः, जंगली बनाम लख्मी चंद (1) का निर्णय सही ढंग से तय नहीं हुआ प्रतीत होता है। इन निष्कर्षों के मद्देनजर, इस अपील को खारिज किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि खसरा संख्या 871 और 877 बेचे जाने के दौरान लापरवाही से खसरा संख्या 871 और 872 के लिए मुकदमा लाया गया था। ट्रायल जज ने केवल खसरा नंबर 871 के संबंध में मुकदमे का फैसला सुनाया था, क्योंकि उनकी राय में खसरा नंबर 877 के संबंध में कोई वैध मुकदमा नहीं लाया गया था। निचली अपीलीय; न्यायालय ने माना कि उसने संशोधन की अनुमति दे दी होती, लेकिन चूंकि मुकदमा अन्य आधारों पर खारिज किया जा रहा था, इसलिए संशोधन के लिए आवेदन पर कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया गया, जो वास्तव में 10 फरवरी, 1962 को उसके सामने दिया गया था। इस संशोधन के खिलाफ प्रतिवादियों द्वारा कभी कोई आधार नहीं उठाया गया, जिसे निचली अपीलीय अदालत ने वस्तुतः अनुमति दे दी थी।

इन परिस्थितियों में, हम वादी पक्ष को उस संशोधन की अनुमति देने के लिए एक औपचारिक आदेश देते हैं जो वास्तव में निचली अपीलीय अदालत में प्रस्तुत आवेदन में मांगा गया था, और वास्तव में इस पाठ्यक्रम पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है और वास्तव में न ही कोई उल्लेख है। अपील के आधार पर और न ही बार में श्री दलीप चंद गुप्ता द्वारा संबोधित तर्क में।

परिणामस्वरूप, यह अपील खारिज कर दी जाती है और प्रीएम्प्टर्स के मुकदमे पर पूरी तरह से फैसला सुनाया जाता है। इन परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

पी एंडिट, जे.-संदर्भित आदेश के अंत में, फाल्शॉ, सी.जे., जिनके साथ खन्ना, जे. ने सहमति व्यक्त की, ने निम्नानुसार कहा: -

“वैकल्पिक मामले में एक कठिन बिंदु इस बिंदु पर भी उठता है कि क्या वादी ने अन्यथा धारा 15 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के तहत इंद कौर के हिस्से के संबंध में छूट का अधिकार प्राप्त किया है- ऐसा प्रतीत होता है वर्तमान मामला यह है कि इंद कौर की ज़मीन का हिस्सा उसके पति से आया था और उप-धारा (2) (बी), जैसा कि 1960 में संशोधित किया गया था, पढ़ें-

"जहां बिक्री भूमि या संपत्ति की एक महिला द्वारा की जाती है, जिसमें वह अपने पति के माध्यम से या अपने बेटे के माध्यम से सफल हुई थी, यदि बेटे को अपने पिता से बेची गई भूमि या संपत्ति विरासत में मिली थी, तो पूर्व-खाली का अधिकार निहित होगा-

सबसे पहले, ऐसी महिला के बेटे या बेटी में ”

1964 के अधिनियम XIII द्वारा इसमें संशोधन किया गया ताकि अब यह पढ़ा जाए|

“सबसे पहले, महिला के ऐसे पति के बेटे या बेटी में।” यदि पहले खंड को शाब्दिक रूप से समझा जाता है जैसा कि 1960 में संशोधन के बाद था, तो वादी, इंद्र कौर के सौतेले बेटे होने के नाते, इस तथ्य के बावजूद उनके द्वारा बेची गई भूमि के संबंध में पूर्व-खाली अधिकार का आनंद नहीं लेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका का इरादा यह था कि इस प्रकार के मामले में बेटे इस तथ्य से

पूर्व-खाली का अधिकार प्राप्त करने के हकदार थे कि भूमि उनके पिता की थी। इस प्रकार सवाल उठता है कि क्या 1964 का संशोधन केवल मूल इरादे का स्पष्टीकरण था और यह भी कि क्या, यदि ऐसा नहीं था, तो संशोधन के आधार पर वादी के पक्ष में इस अपील में मौजूदा डिक्री को अभी भी बरकरार रखा जा सकता है।

यह सवाल कि क्या इस मामले में वादी को अपनी सौतेली मां इंद कौर द्वारा अपने पति तरलोक सिंह के माध्यम से विरासत में मिली संपत्ति की बिक्री से पहले छूट देने का अधिकार था, हमारे सामने काफी विस्तार से बहस हुई थी। . इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट, 1913 की धारा 15(2) (बी) में आने वाले 'बेटा' शब्द में 'सौतेला बेटा' शामिल है या नहीं, जैसा कि इस संशोधन से पहले था। 1964 के पंजाब अधिनियम संख्या XIII द्वारा खंड। प्रारंभ में, मुझे स्वीकार करना होगा, मुझे वादी के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति से सहमत होने में कुछ कठिनाई महसूस हुई, क्योंकि उस समय के क़ानून के अनुसार, पूर्व-मुक्ति का अधिकार 'ऐसी महिला के बेटे या बेटी' को दिया गया था, और नियोजित भाषा वैध रूप से इस निष्कर्ष पर सक्षम थी कि यह केवल ऐसी महिला विक्रेता के शरीर से बेटा होगा, जिसके पास पूर्व-मुक्ति का अधिकार होगा। हालाँकि, 1964 के पंजाब अधिनियम XIII द्वारा इस खंड में बाद के संशोधन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विधायिका का इरादा क्या था और अब मेरा विचार है कि असंशोधित खंड में भी सौतेले बेटे को 'बेटे' में शामिल किया गया था . इस निर्णय पर आने के मेरे कारण ये हैं-

(1) यह सामान्य आधार है कि 'बेटा' शब्द को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है और इसलिए, हमें इसके सामान्य शब्दकोश अर्थ के अनुसार जाना होगा। शॉर्टर ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी 'बेटे' को 'एक पुरुष बच्चे या अपने माता-पिता में से किसी एक या दोनों के संबंध में व्यक्ति' के रूप में परिभाषित करती है। वेबस्टर डिक्शनरी में इसी तरह, इस शब्द की परिभाषा 'अपने माता-पिता या माता-पिता के संबंध में एक पुरुष बच्चे' के रूप में दी गई है। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि इसके सामान्य अर्थ के अनुसार 'बेटे' में 'सौतेला' भी शामिल है।

(2) यदि विधायिका चाहती थी कि इस खंड में 'सौतेले बेटे' को 'बेटे' में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, तो वह अधिनियम में ऐसा कह सकती थी और विशेष रूप से इसके अर्थ पर वह सीमा लगा सकती थी। लेकिन, माना कि, ऐसा नहीं किया गया है।

(3) विधायिका को 'बेटे' और 'सौतेले बेटे' के बीच अंतर जानना चाहिए था। यह जानते हुए कि, यदि उसने सौतेले बेटे को बाहर नहीं रखा है, तो उसका इरादा स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह चाहता था कि ऐसी परिस्थितियों में, सौतेला बेटा भी अपनी सौतेली माँ द्वारा की गई बिक्री का भुगतान करने में सक्षम हो। जहां विधायिका सौतेले बेटे को बाहर करना चाहती थी, उसने वास्तव में क़ानून में ही ऐसा कहा है, उदाहरण के लिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में, धारा 18 में, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पूर्ण रक्त से संबंधित उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकारियों पर प्राथमिकता दी जाएगी आधे खून से संबंधित, यदि रिश्ते की प्रकृति अन्य सभी मामलों में समान है।

(4) धारा 15(2)(बी) पहली बार, 1960 के पंजाब अधिनियम एक्स द्वारा पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट, 1913 में पेश किया गया था। इससे पहले, के संबंध में प्री-एम्प्शन का अधिकार कृषि भूमि और गांव की अचल संपत्ति, जहां बिक्री एकमात्र मालिक द्वारा की गई थी, या संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि या संपत्ति के मामले में, सभी सह-हिस्सेदारों द्वारा संयुक्त रूप से, उत्तराधिकार के क्रम में उस व्यक्ति में निहित किया गया था, लेकिन इस तरह के लिए बिक्री, विक्रेता या विक्रेताओं की मृत्यु पर, बेची गई भूमि या संपत्ति को विरासत में पाने का हकदार होता। दूसरे शब्दों में, यदि बिक्री एमएसटी द्वारा की गई थी। 1960 के पंजाब अधिनियम विधायिका को कानून की इस स्थिति के बारे में तब पता था, जब उसने 1960 के पंजाब अधिनियम संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया।

(5) यह उल्लेख करना उचित है कि वह संपत्ति जो बिक्री की विषय-वस्तु थी। इस उपधारा में, क्या महिला को अपने पति से या अपने बेटे के माध्यम से विरासत में मिला था, जिसने उसे अपने पिता से विरासत में मिला था। ऐसा प्रतीत होता है कि जोर उस स्रोत पर है जहां से बेची गई संपत्ति महिला को विरासत में मिली थी।

यह उप-धारा 2(ए) के प्रावधानों से और भी स्पष्ट होगा जिसके तहत यदि महिला द्वारा बिक्री उस संपत्ति की थी जिस पर वह अपने पिता या भाई के माध्यम से सफल हुई थी, तो छूट का अधिकार उसके भाई या भाइयों को दिया गया था। बेटे, और यदि ऐसी संपत्ति की बिक्री उसके बेटे या बेटी द्वारा की गई थी, क्योंकि उन्हें वह संपत्ति विरासत में मिली थी, तो ऐसी बिक्री को महिला के भाई या उसके भाई के बेटों द्वारा पूर्व-खाली किया जा सकता था। उप-धारा 2 (बी) में पूर्व-खाली का अधिकार दूसरी बात यह है कि यह पति के भाई और ऐसी महिला के पति के भाई के बेटे को दिया गया है, जिसका अर्थ है कि संपत्ति पति के निकट संबंधियों के पास ही रहनी चाहिए। पहले में, अधिकार बेटे या बेटी को दिया जाता है और उनके न रहने पर, दूसरे में उल्लिखित व्यक्तियों को दिया जाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि विधायिका की मंशा यह थी कि पहले ऐसी महिला के शरीर से उसके पति के पुत्र और पुत्रियों को शामिल किया जाए, न कि केवल उसके पुत्र और पुत्री को।

(6) यह उचित नहीं है कि विधायिका का इरादा है कि पति के बेटे या बेटी को, हालांकि एक अलग पत्नी से, उस पति से महिला द्वारा विरासत में मिली भूमि की बिक्री को पूर्व-खाली करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जब स्वीकार किया जाए दूसरे, पति के भाई या पति के भाई के बेटे, जो पति से उसके बेटे या बेटी की तुलना में दूर से संबंधित थे, को ऐसा अधिकार दिया गया था।

(7) 1964 के पंजाब प्री-एम्पशन (संशोधन) अधिनियम XIII द्वारा इस उप-खंड में किए गए संशोधन के बाद, अधिकार महिला के ऐसे पति के बेटे या बेटी में है। अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है कि विधायिका की मंशा शुरू से ही यह थी कि प्रथम के तहत प्री-एम्प्शन का अधिकार महिला विक्रेता के ऐसे पति के बेटे या बेटी को दिया जाना चाहिए। इस संशोधन ने केवल विधायिका की स्थिति और मंशा को स्पष्ट किया है, क्योंकि पहले प्रयुक्त भाषा अन्य व्याख्याओं में भी सक्षम थी। यह इस संशोधन की ओर ले जाने वाले विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से भी स्पष्ट होगा, जहां यह कहा गया था-

“ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब प्री-एम्प्शन (संशोधन) की धारा 15(2) को लागू करने में विधानमंडल की मंशा थी

अधिनियम, 1960 (1960 का पंजाब अधिनियम संख्या 10), उस संपत्ति के संबंध में पति की संतानों को पूर्व-मुक्ति का अधिकार प्रदान करना था, जिस पर एक महिला ऐसे पति के माध्यम से सफल हुई थी। परन्तु धारा 15(2) के खण्ड (बी) में प्रयुक्त शब्दों से यह आशय स्पष्ट नहीं है। वर्तमान धारा में ऐसी महिला के किसी अन्य पति से उत्पन्न पुत्र या पुत्री तथा ऐसी महिला के पति के भाई या भाई के पुत्र को भी शामिल किया जा सकता है, सिवाय उस महिला के जिसके माध्यम से वह संपत्ति में सफल हुई है।

प्रावधान में एक और दोष यह है कि एक ही पति की दूसरी पत्नी से होने वाली संतानों को मौजूदा प्रावधानों में इस्तेमाल किए गए शब्दों से बाहर रखा गया है, जिससे ऐसा लगता है कि यह अनजाने में हुआ है।''

चानन सिंह और अन्य बनाम श्रीमती में। जय कौर, आर.एस.ए. 1960 का 345, जिसका निर्णय मेरे द्वारा 26 अक्टूबर 1960 को, 1960 के पंजाब प्री-एम्पशन (संशोधन) अधिनियम एक्स के लागू होने के बाद और 1964 के संशोधन पेश होने से बहुत पहले, धारा 15(2)(बी) सबसे पहले, मैंने माना था कि प्रीएम्प्शन का अधिकार केवल ऐसी महिला के गर्भ से पैदा हुए बेटे या बेटी को दिया गया था। उस मामले में, महिला की सौतेली बेटी अपनी सौतेली माँ द्वारा बिक्री से पहले छूट चाहती थी, और मैंने माना था कि उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, फर्स्ट में प्रयुक्त भाषा उस निर्माण में सक्षम थी जो मैंने फर्स्ट में आने वाले 'ऐसी महिला की बेटी' अभिव्यक्ति पर रखी थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि दूसरे में, पति के भाई के बेटे को न कि ऐसी महिला को पति के भाई की बेटी को प्री-एम्प्शन का अधिकार दिया गया था। मेरे इस निर्णय की पुष्टि 10 मई, 1965 को लेटर्स पेटेंट बेंच द्वारा की गई। फैसले के दौरान, विद्वान न्यायाधीशों ने कहा-

“इन प्रावधानों को पढ़ने पर (जैसा कि वे 1964 के संशोधन से पहले थे) स्पष्ट रूप से विद्वान एकल न्यायाधीश के पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वादी सुश्री। जय कौर एमएसटी के शरीर से नहीं हैं। सोभी के पास चुनौती की कोई रोशनी नहीं थी।”

हालाँकि, लेटर्स पेटेंट अपील को 1964 के पंजाब अधिनियम XIII द्वारा पेश किए गए संशोधन के कारण अनुमति दी गई थी, जिसमें महिला के ऐसे पति के बेटे या बेटी को प्री-एम्प्शन का अधिकार दिया गया था।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्ण वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा

मेंइसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक

और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णयर्ण का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुकत रहेगा ।

Checked By:

Prerna Arya

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy

Chandigarh